नागरिकता कानून और कांग्रेस का बेजा विरोध

रमेश कुमार दुबे

जो कांग्रेस पार्टी अपने स्थापना दिवस पर संविधान की दुहाई देते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का विरोध कर रही है, वही कांग्रेस इन प्रावधानों की जननी रही है. नेहरू-लियाकत समझौता, असम में एनआरसी और 2011 में एनपीआर की शुरूआत कांग्रेस की ही देन हैं. कांग्रेस पार्टी की भांति उसके युवा नेता भी इन मुद्दों पर झूठ बोलकर भ्रम फैला रहे हैं. यह स्थिति तब है जब राफेल विमान समझौते पर झूठ फैलाने के कारण राहुल गांधी उच्चतम न्यायालय के समक्ष माफी मांग चुके हैं.

आजादी के सत्तर साल तक कांग्रेस बिजली, सड़क, पानी के नाम पर वोट मांगती रही, लेकिन ये बुनियादी सुविधाएं आम लोगों से दूर ही रहीं. दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज पांच साल के भीतर करोड़ों सुविधाविहीन लोगों तक बिजली, सड़क, शौचालय, रसोई गैस, बैंक, बीमा जैसी सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के पहुंचा दी. सबसे बड़ी बात यह रही कि इन सुविधाओं को हासिल करने के लिए गरीबों को किसी प्रकार की रिश्वत नहीं देनी पड़ी और गरीबों को सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली योजनाएं तय समय से पहले पूरी हुईं. इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हर गांव तक बिजली पहुंचाने की कामयाब योजना रही. इसका परिणाम यह हुआ कि 2019 के लोक सभा चुनाव में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया.

चूंकि अब बिजली, सड़क, शौचालय, रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं लगभग सभी भारतीयों तक पहुंच चुकी हैं, तो विपक्ष के पास चुनावी वायदे के लिए कुछ बचा ही नहीं है. यही कारण है कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति पर उतर आया है. मोदी सरकार द्वारा पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ने मोदी विरोधी राजनीति को एक नया आयाम दे दिया है. इन मुद्दों पर सबसे मुखर विरोध कांग्रेस पार्टी का रहा है जिसने 1947 से ही लगातार धार्मिक प्रताड़ना से पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने का समर्थन किया. 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते की तो नींव ही शरणार्थियों को नागरिकता देने पर थी. इसी तरह उच्चतम न्यायालय के आदेश से असम में लागू हुए एनआरसी का कांग्रेस ने समर्थन किया है. इतना ही नहीं 2011 की जनगणना के समय राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरूआत भी कांग्रेस नीति संप्रग सरकार के दौरान हुई थी. स्पष्ट है इन मुद्दों पर कांग्रेस का विरोध अपनी ही नीतियों की आलोचना करने वाला है.

18 दिसंबर 2003 को राज्य सभा में विपक्ष के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाजपेयी सरकार में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से कहा था मैं शरणार्थियों से हो रहे बर्ताव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं "देश के बंटवारे के बाद बांग्लादेश जैसे देशों में अल्पसंख्यकों को आघात का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया ज्यादा उदार होनी चाहिए." अगस्त 2012 में कई भाजपा सांसदों द्वारा लोक सभा में पूछे गए लिखित सवाल के जवाब में यूपीए सरकार ने बताया था कि पांच साल की उम्र के ऊपर के सभी लोगों की उंगलियों और दोनों आंखों की पुतलियों के निशान लिए जांएगे. एनपीआर डाटा से आधार को जोड़ा जाएगा और ऐसे नामों के साथ तैयार लिस्ट को समाज, समुदाय, ग्राम सभा, वार्ड समिति के बीच जारी किया जाएगा. उत्तर में यह भी बताया गया है कि एनपीआर कार्ड मिलने का अर्थ यह नहीं होगा कि हर कोई भारतीय नागरिक है.

जो कांग्रेस धर्म के आधार पर भेदभाव झेल रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की मुखर समर्थक रही हो वही कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम पर हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है तो इसका कारण वोट बैंक की राजनीति ही है. दरअसल अपनी सिमटती राजनीतिक जमीन को देखते हुए कांग्रेस समझ गई है कि सकारात्मक आधार पर मोदी सरकार का विरोध करके सत्ता में आना मुश्किल है. इसीलिए वह अपने सिमटते जनाधार को धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देकर मजबूत

बनाने की कवायद में जुटी है, लेकिन ऐसा करते समय कांग्रेस भूल जाती है कि इतिहास को कुछ समय के लिए झुठलाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता. यही कारण है कि इन मुद्दों पर कांग्रेस की असलियत सामने आने के बाद उसके विरोध की आवाज मंद पड़ गई.

कांग्रेस ही नहीं कई क्षेत्रीय दल भी इन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कांग्रेसी कवायद में एक साथ खड़े हैं. इसका कारण है कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई विकास की राजनीति का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी भारतीयों तक पहुंचा हैं इसलिए जाति की राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों के पास अगड़े, पिछड़े, दलित जैसे संकीर्ण आधारों पर राजनीति चमकाने के मौके नहीं रह गए हैं. यही कारण है कि वैचारिक रूप से कांग्रेस विरोधी होते हुए भी कई क्षेत्रीय दल मोदी विरोध के नाम पर कांग्रेस के साथ नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं.

कांग्रेस की झूठ की राजनीति 70 साल तक इसलिए कामयाब रही क्योंकि उसके झूठ को पकड़ने और सामने लाने वाला सशक्त विकल्प नहीं था. अब मोदी सरकार विकास की राजनीति के जरिए कांग्रेस की असलियत उजागर कर रही है इसलिए उसकी राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है. नागरिकता कानून पर भी कांग्रेस की असलियत सामने आने पर उसकी विरोध की राजनीति उलटी पड़ती जा रही है.

(लेखक केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारी हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)